(ख) यदि हा, तो इस सम्बन्ध मे किए गए निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार का विचार इसे कब तक क्रियान्वित करने का है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ एच मोहसिन):(क) और (ख) सूचना एकत्रित जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्वतंत्रता सेनानी ससद सदस्यो और राज्य विधान मण्डलो के सदस्यो को पेंशन देना

1582 श्री रामावतार शास्त्री: क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 30 जून, 1973 तक स्वतत्रता सेनानी पेशन के लिए आवेदन पत्र देने वाले ससद सदस्यो और राज्य विधान मण्डलो के सदस्यो की राज्यवार सख्या क्या है तथा उनके नाम क्या है,

(ख) जिन लोगो को पेशन की स्वीकृति मिल चुकी है उनके राज्यवार नाम क्या है, और

(ग) शेष व्यक्तियो के बारे मे सरकार का कब तक निर्णय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) ससद सदस्यो और राज्य विधान मण्डलो के सदस्यो के नामो और उन राज्यो के नाम जिनसे उनका सम्बन्ध है, का एक विवरण सभा पटल पर रखा है । [ग्रन्थालय मे रखा गया । देखिये सख्या LT 5273/73]

(ख) अभी तक किसी ससद सदस्य अथवा किसी विधायक को पेशन स्वीकृत नही की गई है । किन्तु तमिलनाडु के ससद सदस्य (लोक सभा) स्व० श्री के० बालाधन्दयुधाम की विधवा को 150 रुपये मासिक पेशन स्वीकृत की गई है । इसमे 50 रु० मासिक अविवाहित पुत्री के लिए पेशन है जो उसके विवाह तक मिलती रहेगी और 100 रु० मासिक पेशन विधवा के लिए है जो उसको जीवन काल तक मिलती रहेगी ।

(ग) ऐसे मामलो मे पेशन,अ।वेदक की यह घोषणा प्राप्त होने पर की जायेगी कि उसकी वार्षिक आय 5000 रु० से कम हो गई है, स्वीकृत की जायेगी । बशर्ते कि पात्रता की अन्य शर्तें पूरी हो ।

स्वतंत्रता सेनानियो की जीवन-झाकिया

1583. रामावतार शास्त्री : क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने स्वतत्रता सेनानियो की जीवन झाकी प्रकाशित करने सम्बन्धी कोई योजना बनाई है,

(ख) यदि हा, तो उसकी मुख्य बाते क्या है, और

(ग) सरकार का विचार इस योजना को कब से क्रियान्वित करने का है ?

गृह मत्रालय मे उप-मत्री श्री एफ एच० मोहसिन) : (क) से (ग) 1960 मे राज्य सरकारो/सघ राज्य क्षेत्र प्रशासनो से उनके अपने क्षेत्रो के स्वतत्रता सेनानियो की एक "परिचय पुस्तक" निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध किया गया था । इन पुस्तको मे स्वतत्रता सेनानियो की जीवन झाकी तथा उनके जीवन की मुख्य उपलब्धिया समाहित करनी थी । जबकि बहुत थोडे राज्य सरकारो/सघ राज्य